मुद्रस्फीति के प्रभाव

1. **अमीर और गरीब**– मुद्रास्फीति धन का पुनर्वितरण अमीरों के सापेक्ष गरीबों में कम होता है, अर्थात् मुद्रास्फीति में अधिक मुद्रापूर्ति अमीरों को अधिक एवं गरीबों के पास कम होती है। जिसके परिणाम स्वरूप अमीरों को लाभ एवं गरीबों को हानि होती है।

2. **उपभोक्ता और उत्पादक**– मुद्रास्फीति में कुछ वस्तुएँ खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है अर्थात् उपभोक्ताओं को वस्तु का मूल्य अधिक देना होता है, जिससे उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है।

3. **निश्चित और परविर्तनशील आय-समूह**– निश्चित आय-समूह (वेतन भोगी, पेंशन भोगी आदि) एवं अनिश्चित आय समूह सेवा प्रदान करने वाले या व्यापारी वर्ग एवं व्यवसायी वर्ग।

   मुद्रास्फीति में लचीली आय-समूह के लोगों को लाभ होता है जबकि निश्चित आय-समूह को हानि।

4. **लेनदार (ऋणदाता) & देनदार (ऋणी)**– मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है जिससे ऋणी द्वारा ऋणदाता को वापस की गयी मुद्रा से उतना लाभ प्राप्त नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति ऋणी के अनुकूल एवं ऋणदाता के प्रतिकूल।

5. **छोटे किसान एवं बड़े किसान**– ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, छोटे किसान होते हैं। ये स्वयं के लिए खेती करते हैं। एवं बड़े किसान उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं तथा लाभ कमाते हैं।

6. **डिबेंचर (ऋण पत्र) / बांड धारक & इक्विटी (Shace) धारक**– Bond धारक वे निवेशक होते हैं, जिन्हें अपनी मूल रकम पर एक निश्चित ब्याज प्राप्त होता है एव इक्विटी धारक को अनिश्चित आय, जो मुद्रास्फीति में अधिक लाभ लेते हैं।

7. **भुगतान संतुल**– यह किसी देश के होने वाले आयातों-निर्यातों से संबंद्ध है। मुद्रास्फीति के समय में निर्यात कम एवं आयात अधिक । सिजके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल भुगतान संतुलन (Im > Ex) होता है।

8. **विदेशी विनिमय दर**– अधिक आयात के कारण घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य कम हो जाता है, अर्थात् मुद्रा मूल्यह्रास होता है।

9. **रोजगार पर**– अल्पकालीन मुद्रास्फीति में रोजगार में वृद्धि एवं दीर्घकालिन में रोजगार कम होता है।

10. **बचत पर**– मुद्रास्फीति में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने से व्यय अधिक होने के कारण बचत की सम्भावना कम होती है।

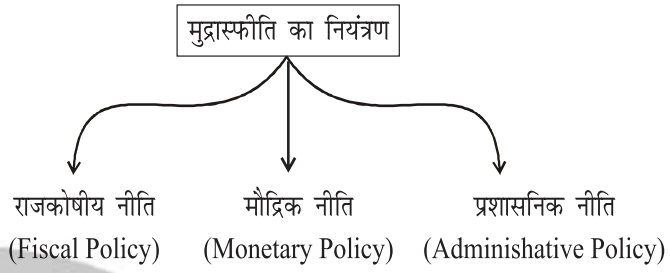

राजकोषीय नीति

सरकार के द्वारा राजस्व एवं व्यय से संबंधित नीति है। इसको वित्त मंत्रालय तैयार करता है एवं इसे बजटरी नीति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार अपने व्यय/खर्च एवं आय के द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मापदण्डों का परिचालन करता है।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य–

1. **कीमत स्थिरता**– सरकार अपने व्यय एवं राजस्व के द्वारा कीमत के चलन को नियंत्रित करती है।
2. **आर्थिक संवृद्धि**– राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना। अर्थात उत्पादन-स्तर में वृद्धि करना। जिससे सरकार निवेश की दरों को बढ़ाकर एवं उत्पादकों को प्रोत्साहित करके प्राप्त करती है।
3. **आय की असमानता को कम करना**– अविकसित एवं विकासशील देशों में आय का वितरण असमान होता एवं इस नीति के द्वारा सरकार यह प्रयत्यन करती है कि आय को समान रूपी तरीके से वितरित कर सकें। एवं इसे प्राप्त करने के उपाय निम्नलिखित हैं-
   (i) अमीरों पर अधिक कर लगाना।
   (ii) निर्धन वर्ग हेतु करों की दर कम करना।
   (iii) विभिन्न योजनाओं के द्वारा निर्धनों को वित्तीय लाभ देना।
4. **रोजगार के अवसर प्रदान करना**–सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से रोजगार के अवसर बढ़ाये जाते हैं। जैसे-
   (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित करके।
   (ii) निजी क्षेत्र को साब्सिडी देकर एवं करो की दर कम करके।

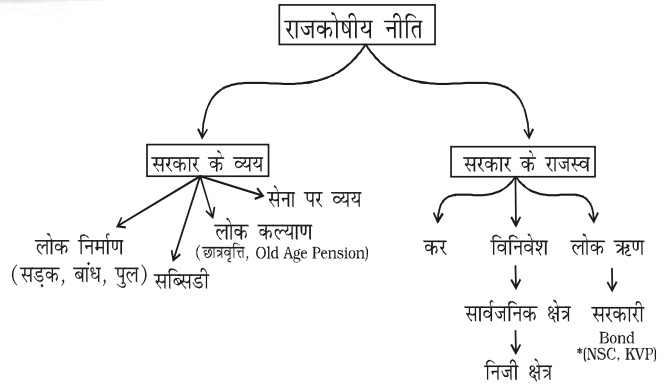

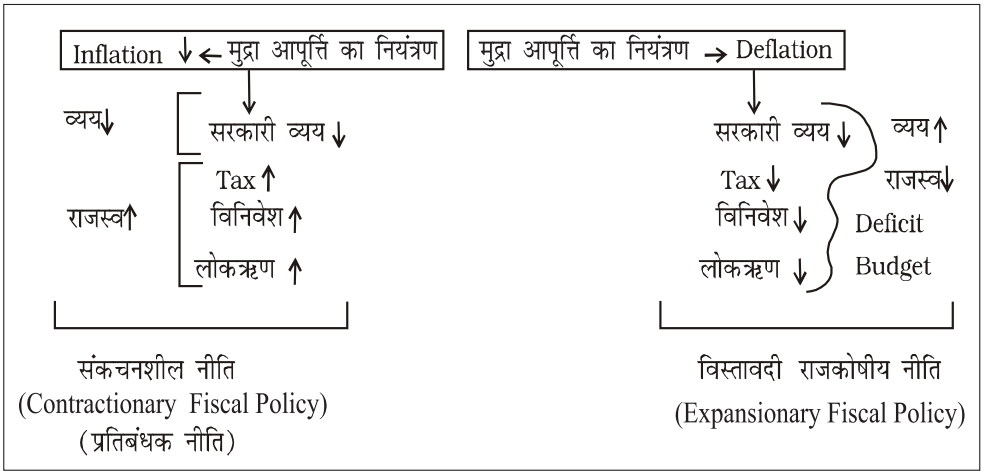

Neutral Fiscal Policy– इसमें सरकार अपने व्यय एवं राजस्व को नियंत्रित रखती है।

Subprime Lending / Crises– यह एक अवस्था है, जब किसी देश की बैंक उन लोगों को ऋण दे देती है जिनके पास ऋण वापस करने की क्षमता नहीं होती। 2008 में इसे USA में देखा गया, जिसके कारण वहाँ की बैंकों पर Negative प्रभाव पड़ा। लेमेन ब्रदर्स जैसी Bank बंद हो गयी।

Fiscal Cliff– यह Subprime संकट से संबंधित है। अमेरिका की कांग्रेस ने आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए मंदी की अवधि के दौरान कर -कटौती के लिए कई कानून बनाये, लेकिन एक समय-सीमा तय कर दी थी (31 Dec. 2012) की आधी रात तक)

★ 1 Jan 2023 से उच्च कर प्रारंभ कर दिये।

★ उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक स्थिति को Fiscal Cliff कहते हैं।

वित्तीय लाभ देना (Fiscal Drag)– इसमें सरकार अधिक कर राजस्व (प्रगतिशील कर) अर्थात् मुख्य रूप से आयकर के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है।

★ इसमें अमीरों का पैसा गरीबों में वितरित किया जाता है।

राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidiction) – जब सरकार अपने घाटे एवं ऋण को नियंत्रित करे, इसे राजकोषीय समेकन कहते हैं।

Fiscal Glide– राजकोषीय समकेन को चरणवार तरीके से करना, Fiscal Glide कहलाता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मुद्रास्फीति तब होती है जब संपूर्ण आपूर्ति होती है
(a) कुल मांग से अधिक (b) कुल मांग से कम
(c) कुल मांग के बराबर (d) इनमें से कोई नहीं

2. भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है?
(a) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(b) थोक मूल्य सूचकांक
(c) श्रमिकों का जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक
(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. खाद्य वस्तुओं का 'उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक' (CPI) में भार (Weightage) उनके 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में दिए गए भार से अधिक है।
2. WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है।
3. भारतीय रिवर्ज बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारिण का आधार है–
(a) राष्ट्रीय आय (b) उपभोक्ता कीमत सूचकांक
(c) जीवन स्तर (d) प्रति व्यक्ति आय

5. कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है–
(a) केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से
(b) खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से
(c) केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से
(d) खाद्य मद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से

6. भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थापन/कार्यालय जारी करता है?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(c) वित्त मंत्रालय
(d) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

7. थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार (Weightage) दिया जाता है?
(a) खाद्य पदार्थ क्षेत्र
(b) गैर-खाद्य पदार्थ क्षेत्र
(c) ईंधन, पावर, लाईट एवं ल्यूब्रीकेंट्स
(d) विनिर्मित उत्पाद